नजरिया

भोपाल रविवार 22 नवंबर 2020

दैनिक जागरण

यदि आप बार-बार शिकायत नहीं करते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। -बर्नार्ड एम. बारुच

काश्मीर में स्वस्थ राजनीति का दौर चले

ललित गर्ग

लेखक कई अखबारों के स्तंभलेखक हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में नैशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम रूपी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) नामक राजनीतिक मोर्चा पर तीखा हमला बोलते कहा कि गुपकार गैंग जम्मू-कश्मीर को फिर से आतंक, हिंसा, अशांति और उत्पात के दौर में ले जाना चाहता है। यह गुपकार राजनीतिक दल राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ रहा है। अभी तक कांग्रेस का इनके साथ घोषित तौर पर कोई समझौता नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सीटों का तालमेल होने की चर्चा है। गुपकार की बढ़ती सक्रियता से कहीं कश्मीर में शांति, अमन एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर फिर से अंधेरे ना छाये? गृहमंत्री ने गुपकार को एक राजनीतिक दल की बजाय एक गैंग कहकर संबोधित किया है, इससे भले ही कुछ लोग सहमत न हो, लेकिन इसे गैंग कहने के कुछ तो कारण रहे होंगे। एक पूरा वातावरण जो मिल रहा है, परिवेश निर्मित किया जा रहा है, वह आतंक एवं अशांति को बढ़ाने वाला है, घटाने वाला बिलकुल नहीं लगता। क्यों आवश्यकता है कि राष्ट्र-विरोधी, आतंक एवं अशांतिमूलक गतिविधियों एवं विचारों को संक्रामक बनाया जाए? प्रांत की शांति व्यवस्था एवं विकास की प्रक्रिया को बाधित किया जाये। गुपकार की आक्रामक एवं राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के बीच हम कल्पना कैसे करें कि हिंसा नहीं बढ़ेगी, आतंक नहीं पनपेगा और अशांति नहीं बढ़ेंगी? इसलिए सबसे पहले ध्यान देना है कश्मीर के परिवेश पर, वहां के वातावरण पर। वहां के स्थानीय राजनीतिक दलों ने अपने चारों ओर किस प्रकार के वातावरण का निर्माण कर रखा है? वह जब तक नहीं बदलेगा, तब तक हिंसा-आतंक को उत्तेजना देने वाली घटनाएं और निमित्त उभरेंगे।

आतंक एवं हिंसाग्रस्त इस प्रांत में शांति स्थापना के लिये भारत सरकार के प्रयत्न निश्चित ही जीवंत लोकतंत्र का आधार बने है। जरूरत है कश्मीर में राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक संकीर्णता की तथाकथित आवाजों की बजाय सुलझी हुई सभ्य राजनीतिक आवाजों को सक्रिय होने का मौका दिया जाए, विकास एवं शांति के नये रास्ते उद्घाटित किये जाये, इसी दृष्टि से गृहमंत्री का गुपकार पर खास तौर पर हमलावर होना स्वाभाविक है। अगर ये दल राज्य में अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं तो उनकी इस मांग से किस तरह और क्यों सहमत हुआ जा सकता है। भारत का संविधान और यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की इजाजत देती है, लेकिन उनकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां एवं बयान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। केन्द्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी यह कहती रही है कि अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधान खत्म करने का फैसला राज्य की जनता के हित में किया गया है, जिसकी लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब चुनाव वह उपयुक्त मौका है जब भाजपा के कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को इस फैसले की खूबियां समझा सकते हैं और उन्हें समझाना भी चाहिए। जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक संगठनों की अलोकतांत्रिक गतिविधियों एवं प्रांत में आतंक-अशांति एवं हिंसा को बल देने वाले बयानों एवं मनसूंबों का भी बेपर्दा करना

चाहिए। इसी से वहां लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा। दूर बैठकर भी हर भारतीय इस बात को गहराई से महसूस कर रहा है और देख रहा है कि जम्मू-कश्मीर में शांति, सौहार्द, विकास एवं सह-जीवन का वातावरण बन रहा है। वहां संविधान के साये में लोकतंत्र प्रशंसनीय रूप में पलता हुआ दिख रहा है। लेकिन गुपकार में सत्ताविहीन असंतुष्टों की तरह आदर्शविहीन असंतुष्टों की भी एक लम्बी पंक्ति है जो सत्ता की लालसा में शांति कम, खतरे ज्यादा उत्पन्न कर रही है। वे सब चाहते हैं कि हम आलोचना करें, अच्छाई में भी बुराई खोजे, शांति एवं सौहार्द की स्थितियों को भी अशांत बताये, पर वे शांति का, सुशासन का, विकास का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। हम गलतियां निकालें पर दायित्व स्वीकार नहीं करें। ऐसा वर्ग आज जम्मू-कश्मीर के लिये विडम्बना एवं त्रासदी बने मुद्दों को लेकर एक बार फिर सक्रिय है। वे लोग अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग करने में अक्षम है, इसलिये स्थानीय निकाय के चुनावों में लोकतांत्रिक अधिकारों को आधार बनाकर अस्तव्यस्तता एवं अशांति को बढ़ाने में विश्वास करते हैं।

भले ही इस राज्य में उग्रवाद के चरम उठान के दिनों में भी गुपकार से जुड़ी पार्टियां न केवल चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी रहकर राज्य में सरकार चलाती रही हैं बल्कि इनके सैकड़ों नेता-कार्यकर्ता आतंकी हमलों में मारे गए हैं और अलग-अलग समय में ये केंद्र सरकार का भी हिस्सा रही हैं, लेकिन यह भी बड़ा सच है कि इन्होंने आतंकवाद को पनपने का अवसर देते हुए, अशांति का वातावरण बनाते हुए एवं विकास को अवरूद्ध करके ही अपनी राजनीतिक हितों की रोटियां सेकी है। यह भी एक सच है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन दलों के प्रमुख नेता कश्मीर को लेकर भारत के पक्ष का समर्थन करते रहे हैं। आज भी ये स्थानीय चुनावों में पूरी शिद्दत से शामिल हो रहे हैं, चुनाव बहिष्कार की बात नहीं कर रहे। लेकिन ये दल राज्य में अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं, पाकिस्तान के सूर में सूर मिलाते हैं तो किस तरह उनसे सहमति बने? गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर के इन राजनीतिक संगठनों को आपराधिक गिरोह या गैंग करार किया है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति प्रतीत नहीं होती है। यह एक साहसभरा कदम है, साहस का परिचय तो कश्मीर में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद-370 को हटाकर भी दिया, उससे भी अधिक उसने शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने की स्थितियों को निर्मित कर परिपक्वता का परिचय दिया है। अनुच्छेद-370 के हटने के बाद की नवीन स्थितियों में कश्मीर की जनता ने राहत की सांस ली है, नवीन परिवेश में वहां किसी बड़ी अप्रिय, हिंसक, आतंकी एवं अराजक स्थिति का न होना, वहां की जनता का केन्द्र सरकार में विश्वास का परिचायक है।

कृषि विकास को चाहिए ठोस पहल

ब्रजेश झा

लेखक कृषि विशेषज्ञ हैं।

कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान सिर्फ 15 प्रतिशत है, लेकिन करीब 45 से 60 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं ऐसे में कृषि का यदि अच्छे से विकास हो, किसानों को उनकी उपज का अच्छा पैसा मिले, तो कृषि कार्यों से जुड़े 45 से 60 प्रतिशत लोगों की जिंदगी बेहतर हो जायेगी यह अच्छी बात है कि कोरोना काल में लॉकडाउन लगने या जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बंद होने या अन्य कारणों से कृषि बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, जैसाकि दूसरे क्षेत्रों के साथ हुआ है कृषि में संभावना है और इसकी बेहतरी के लिए जरूर सोचा जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए सिंचाई, तकनीक, बाजार आदि से संबंधित समस्याओं को दूर करना होगा हमारी करीब 50 प्रतिशत भूमि ही अभी तक सिंचित हो पायी है, जबकि 1980 तक एक तिहाई भूमि सिंचित हो चुकी थी इस लिहाज से करीब 40 वर्षों में मुश्किल से 17 प्रतिशत और भूमि को ही हम

कृषि में बेहतरी के साथ-साथ ग्रामीण विकास भी बहुत जरूरी है ग्रामीण विकास नहीं होने से यहां शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम तरह की परेशानियां हैं, इस कारण लोग गांवों में रहना नहीं चाहते हैं. खासकर जो थोड़े से भी पढ़-लिखे हैं वे आस-पास के शहरों में पलायन कर जाते हैं।

सींच पाये हैं, जो बेहद धीमी गति है हमारी सिंचाई अब ट्यूबवेल आधारित हो गयी है, इस कारण उन इलाकों का भूमिगत जलस्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे चला गया है, जो पहले जल संपन्न माना जाता था इससे यहां भी जल समस्या उत्पन्न हो गयी है इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन के कारण कभी चार-पांच दिन तक इतनी ज्यादा बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है और फिर पांच-सात, 15 दिन तक पानी ही नहीं बरसता और सूखा हो जाता है एक्सट्रीम वेदर के कारण खेती काफी प्रभावित हो रही है जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें अभी वृद्धि होगी इसलिए जल संरक्षण संरचना को बनाया और बचाया जाना बहुत जरूरी है आज जो भी तालाब या कुएं बचे हैं उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है, क्योंकि जब इन जल निकायों में बरसात का पानी जमा होगा, तो वह भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करेगा और उसका इस्तेमाल सिंचाई में भी हो सकेगा ये जल संरक्षण संरचना अत्यधिक वर्षा के कारण आनेवाली बाढ़ को भी रोकने में सहायक सिद्ध होंगे मनरेगा के तहत यह कार्य हो भी रहा है लेकिन इसकी गति और संख्या बढ़ाने की जरूरत है माइक्रो इरिगेशन की बहुत जरूरत है, लेकिन अभी पूरे भारतवर्ष के करीब 10 प्रतिशत क्षेत्र में ही यह पहुंच पाया है, जबकि हमारे देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पानी की बहुत कमी है देशभर की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना होगा हमारे देश में करीब 86 प्रतिशत छोटे या सीमांत किसान हैं जिन्हें घर-परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के अलावा आमदनी के दूसरे स्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में इस दूसरे स्रोत की कमी हो गयी है, इस कारण ये किसान बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं अपनी जमीन की सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं एक तरह से गैरहाजिर भू-मालिकों की संख्या ज्यादा हो गयी है इस परेशानी को दूर करने के लिए हमारा लैंड रिकॉर्ड ठीक होना जरूरी है, क्योंकि इससे फिर हमारा लैंड मार्केट ठीक होगा खेती से संबद्ध और गैर-कृषि क्षेत्रों का गांव के आस-पास होना भी बहुत आवश्यक है संबद्ध क्षेत्रों जैसे पशु पालन में तो काफी काम हुआ है लेकिन मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशमकीट पालन के क्षेत्र में अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है, जबकि इनमें काफी संभावनाएं हैं तो इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की जरूरत है गांव के नजदीक के जो शहर हैं वहां भी नॉन-एग्रीकृचर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित चीजों की व्यवस्था करने की जरूरत है, जिससे किसानों को काम की तलाश में बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े दूसरे, किसानों को तकनीकी माध्यम से किसानी की जानकारी देना आवश्यक है आजकल मोबाइल से यह हो रहा है, लेकिन अभी इसकी पहुंच ज्यादा नहीं है इसे सही तरीके से और ज्यादा विस्तार देना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ सकें इसके लिए संबंधित इलाके के कृषि विश्वविद्यालय को काफी गंभीरता दिखानी होगी हालांकि, इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार संविदा खेती का नया कृषि कानून लेकर आयी है यह एक अच्छा कदम है बाजार से जुड़े दो कानून भी अभी सरकार लेकर आयी है इसमें निजी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है और एपीएमसी मार्केट की मोनोपॉली को खत्म की गयी है निजी लोगों के आने से निवेश ज्यादा होगा और किसानों को ज्यादा विकृप भी उपलब्ध हो सकता है साथ ही, उत्पादों के रख-रखाव और प्रसंस्करण के लिए भी नये उपाय किये जा सकेंगे कृषि विकास के अलावा, कृषि में अच्छे लोगों का रहना बहुत जरूरी है गांव से लोगों का पलायन न हो इसके लिए इंफ्रॉस्ट्रक्चर पर ध्यान देना, उसे बेहतर बनाना बहुत जरूरी है मनरेगा के विस्तार से इसे अच्छा किया जा सकता है कृषि में बेहतरी के साथ-साथ ग्रामीण विकास भी बहुत जरूरी है ग्रामीण विकास नहीं होने से यहां शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम तरह की परेशानियां हैं, इस कारण लोग गांवों में रहना नहीं चाहते हैं. खासकर जो थोड़े से भी पढ़-लिखे हैं वे आस-पास के शहरों में पलायन कर जाते हैं. इस समस्याओं के निदान में कितना समय लगेगा, यह अलग-अलग जगह और वहां किस तरह की समस्या है, इस पर निर्भर करता है हां यह जरूर कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे इन समस्याओं का निदान होता जायेगा, संबंधित जगहों पर खेती और ग्रामीण विकास भी बेहतर होता जायेगा।

कांग्रेस को संजीवनी की तलाश

- रशीद किदवई

(राजनीतिक विश्लेषक)

हार चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर कपिल सिब्बल द्वारा की गयी टिप्पणी कांग्रेस की अंदरूनी रस्साकशी का हिस्सा है कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व को लेकर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है कि क्या राहुल गांधी स्वेच्छा से पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेंगे? क्या वे अपने किसी विश्वासपात्र को कांगेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा करेंगे? विरोधी खेमे की यही मंशा है कि राहुल अपनी जगह अपने किसी विश्वासपात्र को खड़ा करें, तो उन्हें चुनौती दी जाए, क्योंकि यदि राहुल खुद चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें हराना मुश्किल होगा कांग्रेस के अंदर जो असंतुष्ट हैं, वे राहुल और सोनिया गांधी को चोट पहुंचाने का एक मौका ढूंढ रहे हैं उसी के तहत चिट्ठी और इंटरव्यू के माध्यम से कांग्रेस की आलोचना की जा रही है जहां तक बिहार चुनाव की बात है, तो इसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत बड़ी नहीं थी दरअसल, बिहार चुनाव की आड़ में असंतुष्टों को कांग्रेस पर हमला करने का बहाना मिल गया है और इसी की आड़ में कांग्रेस नेतृत्व पर प्रश्न उठाया जा रहा है असल में बिहार चुनाव को लेकर असंतुष्ट कांग्रेसियों या विरोधियों का आकलन था कि बिहार में महागठबंधन की जीत होते ही राहुल गांधी को तुरंत पार्टी अध्यक्ष बनाये जाने की कवायद शुरू हो जायेगी।

कांग्रेस के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार, पार्टी की राज्य इकाई के 10 सदस्य मिल कर किसी को भी अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत कर सकते हैं ऐसे में यदि कोई असंतुष्ट अपनी तरफ से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की ठान ले या किसी कद्दावर नेता को खड़ा कर दे, तो यहां राहुल गांधी के लिए समस्या हो जायेगी। राहुल गांधी को उसे दावेदार मानना होगा या उस चुनौती को स्वीकार कर चुनाव लड़ना होगा या फिर उन्हें अपनी तरफ से किसी उम्मीदवार को खड़ा करना होगा ऐसा होने से कांग्रेस में भी नयी शक्ति का संचार होगा इसी वर्ष अगस्त में 23 लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर जब चिट्ठी लिखी थी, तो उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति का पुनर्गठन किया और उसमें से छह-सात असंतुष्टों को, जिनमें गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, आनंद शर्मा आदि शामिल थे, उनको कार्यसमिति में जगह दी इस कदम से असंतुष्ट गतिविधियों पर एक छोटा विराम लग गया था, लेकिन एक बार फिर से यह सब शुरू हो गया है असंतुष्टों को लेकर यह देखना महत्वपूर्ण है कि वे कांग्रेस की मूलभूत संरचना में बदलाव चाहते हैं या फिर कांग्रेस की सत्ता की राजनीति में भागीदार बनना चाह रहे हैं। इस तरह का अंतर्द्वंद कांग्रेस के भीतर चल रहा है कांग्रेस

एक आकलन यह भी हो सकता है कि जब कभी नरेंद्र मोदी और भाजपा से मतदाताओं का मोहभंग होगा, तो वे कांग्रेस की ओर देखेंगे एक सच यह भी है कि कांग्रेस में नेहरू-गांधी परिवार सूत्रधार के रूप में काम करता है और उसकी देशभर में राजनीतिक साख है जब चुनाव प्रचार की बात आती है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार नेहरू-गांधी परिवार को ही प्रचार के लिए बुलाते हैं और उनको लोग सुनने भी आते हैं इनके अलावा, अन्य भारी-भरकम नेताओं की कोई पूछ नहीं होती है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से नेहरू-गांधी परिवार पर बहुत ज्यादा आश्रित है। मेरी समझ से जो असंतुष्ट हैं, वो कहीं न कहीं खुलापन और भागीदारी चाह रहे हैं। सोनिया गांधी और अहमद पटेल का स्वास्थ्य ठीक नहीं होना भी बिहार चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन नहीं करने का एक कारण है। पूरी कांग्रेस में आत्मिवश्वास की कमी है। कांग्रेस को मनोबल वापस प्राप्त करने की जरूरत है।

के भीतर असंतुष्टों का होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि ऐसा होने से पार्टी को ताकत मिलती है यहां प्रश्न है कि जो लोग असंतुष्ट हैं, उनकी मंशा क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं कहीं उनकी मंशा और मुद्दा एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध तो नहीं है, क्या वे कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक नया चेहरा चाह रहे हैं? प्रश्न यह भी है, अगर राहुल गांधी या नेहरू-गांधी परिवार का कोई अन्य सदस्य कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बनता है और कोई पार्टी सदस्य अध्यक्ष बनता है, तो क्या बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल या पुडुचेरी के चुनाव में कांग्रेस जनता को आकर्षित कर पायेगी? क्या संगठन मजबूत होगा? जहां तक संगठन के मजबूत होने की बात है, तो भाजपा का संगठन तो बहुत सालों से मजबूत था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी भी उसे तीन चौथाई बहुमत नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, देश की राजनीति में उनकी पकड़, कश्मीर समस्या के समाधान के लिए धारा 370 को खत्म करना इन सबका उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी प्रभाव पड़ा। आस्था और राजनीति का जिस तरह से अघोषित मिश्रण हुआ है, उसका भी भाजपा को काफी लाभ मिल रहा है कांग्रेस के लिए यह सब करना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि राहुल गांधी ने थोड़ी कोशिश की है कांग्रेस की समस्या महज नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गंभीर है और मुद्दों से भी जुड़ी हुई है एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस के पास इस तरह की बहुत-सी समस्याएं हैं, जो भाजपा के पास नहीं हैं इन सब वजहों से भी कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और नरेंद्र मोदी व अमित शाह की जोड़ी की काट के लिए कांग्रेस को अपने बहुत से वैचारिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा केवल चेहरा बदल जाने से कांग्रेस की समस्या का समाधान नहीं होनेवाला राहुल गांधी का रिकॉर्ड इतना बुरा भी नहीं है, जितना उसे प्रचारित किया जा रहा है इसे ऐसे देखना होगा। गुजरात चुनाव लगभग बराबरी पर खत्म हुआ झारखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, गठबंधन की जीत हुई इसी तरह महाराष्ट्र में भी वह गठबंधन के साथ सत्ता में भागीदार है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी सरकार बन गयी थी असल में लोगों में एक धारणा बन गयी है कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे, तब तक कांग्रेस राजनीतिक रूप से पूर्व की तरह ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पायेगी ऐसे में लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस की वंशवादी राजनीति के पटाक्षेप का समय अब आ गया है ऐसा सोचने वालों में भी दो तरह के लोग हैं, एक वे, जो दिल से ऐसा चाहते हैं और इसके पीछे उनकी मंशा कांग्रेस की बेहतरी ही है वहीं दूसरी तरफ वैसे लोग हैं, जो राजनीति से प्रेरित हैं।

एक आकलन यह भी हो सकता है कि जब कभी नरेंद्र मोदी और भाजपा से मतदाताओं का मोहभंग होगा, तो वे कांग्रेस की ओर देखेंगे एक सच यह भी है कि कांग्रेस में नेहरू-गांधी परिवार सूत्रधार के रूप में काम करता है और उसकी देशभर में राजनीतिक साख है जब चुनाव प्रचार की बात आती है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार नेहरू-गांधी परिवार को ही प्रचार के लिए बुलाते हैं और उनको लोग सुनने भी आते हैं इनके अलावा, अन्य भारी-भरकम नेताओं की कोई पूछ नहीं होती है।

यह दर्शाता है कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से नेहरू-गांधी परिवार पर बहुत ज्यादा आश्रित है मेरी समझ से जो असंतुष्ट हैं, वो कहीं न कहीं खुलापन और भागीदारी चाह रहे हैं सोनिया गांधी और अहमद पटेल का स्वास्थ्य ठीक नहीं होना भी बिहार चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन नहीं करने का एक कारण है पूरी कांग्रेस में आत्मिवश्वास की कमी है कांग्रेस को अपना मनोबल वापस प्राप्त करने की जरूरत है।

अब आ रहा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का दौर

डॉ. स्कन्द शुक्ल

लेखक ख्यातिलब्ध चिकित्सक हैं।

एक ही जीन के अलग-अलग प्रकार अलग-अलग लोगों में मौजूद रहते हैं। जीनों की इस विविधता को विज्ञान की भाषा में जेनेटिक पॉलीमोरफिज्म कहा जाता है। एक ही रोग के रोगियों में एक ही दवा खाने पर प्रभाव अलग-अलग दिखाई देते हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझना बेहतर होगा। प्रज्ञा और उनकी मौसी दोनों को एक ही गठिया रोग है- रुमेटॉयड आर्थराइटिस। दोनों को डॉक्टर ने दवाएं भी लगभग एक-सी लिखीं। लेकिन मौसी को जहां दो महीनों में जोड़ों के दर्द से बहुत आराम मिला, वहीं प्रज्ञा अब तक तकलीफ से जूझ रही हैं। साथ ही वह उलझन में भी हैं कि ऐसा भला क्यों? जिस दवा से मौसी को फायदा हुआ, उसी ने उनके शरीर में काम क्यों नहीं किया?

रामाधीर को कई दिनों से गले में दर्द के साथ खांसी आ रही थी। हरा-पीला बलगम जब बढ़ने लगा, तो उन्होंने अपनी पत्नी की एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अपनी समस्या के लिए कर लिया। लेकिन उसकी दो गोलियां लेते ही उनके शरीर पर तमाम लाल-लाल चकत्ते उभरने लगे और मुंह में छाले पड़ गए। रामाधीर तुरंत अस्पताल भागे, जहां उन्हें बताया गया कि एंटीबायोटिक के कारण उन्हें त्वचा पर साइड इफेक्ट हो रहे हैं। प्रज्ञा और रामाधीर जैसे रोगियों की समस्या वाजिब है। एक ही दवा खाने पर एक ही रोग के रोगियों में प्रभाव अलग-अलग दिखाई देते हैं। कई बार तो एक ही दवा किसी को लाभ पहुंचाती है तो दूसरे में साइड इफेक्ट पैदा कर देती है। ऐसे में क्या कोई ऐसा तरीका है, जिससे इन असफलताओं-समस्याओं को पहले से पहचाना जा सके?

21वीं सदी में हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी व्यक्तिगत चिकित्सा की ओर बढ़ रहे हैं। एक ही रोग से पीड़ित होने के बावजूद प्रत्येक रोगी भिन्न व्यक्ति है। उसके शरीर की कोशिकाओं में मौजूद डीएनए किसी और व्यक्ति से भिन्न है। ऐसे में डीएनए के वे टुकड़े, जिन्हें हम जीन कहते हैं, अलग-अलग व्यक्ति में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। यानी एक ही जीन के अलग-अलग प्रकार अलग-अलग लोगों में मौजूद रहते हैं। जीनों की इस विविधता को विज्ञान की भाषा में जेनेटिक पॉलीमोरफिज्म कहा जाता है। यानी ढेरों जीनों का अलग पालीमोरफिक रूप हम में हरेक की कोशिकाओं में मौजूद है। जीनों के इन्हीं पॉलीमोरफिक प्रकारों के आधार पर हर रोगी में दवा का प्रभाव अलग-अलग आ सकता है।

हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, ताकि बात और स्पष्ट हो। एचआईवी के इलाज में एबैकावीर नामक दवा इस्तेमाल होती है। अन्य एचआईवी-रोधक दवाओं के साथ दुनिया भर के डॉक्टर इसे रोगियों को देते हैं। यह दवा है तो बहुत असरदार, लेकिन लगभग 5-7 प्रतिशत रोगियों में इसके सेवन के बाद थकान, त्वचा पर चकत्ते और दस्त जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अंग प्रत्यारोपण, रूमैटॉयड आर्थराइटिस और अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों में एजाथायोप्रीन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। यह दवा जब खाई जाती है तो शरीर के भीतर एक एंजाइम द्वारा दूसरे सक्रिय रूप में बदलती है। इस एंजाइम का नाम थायोप्यूरीन एस-मिथाइल ट्रांस्फरेज (टीपीएमटी) है। कुछ लोगों में टीपीएमटी बनाने वाले जीन के जो पॉलीमोरफिक रूप पाए जाते हैं, उनके कारण एजाथायोप्रीन अपने सक्रिय स्वरूप में नहीं आ पाती। नतीजन यह अस्थि मज्जा में यों ही जमा होती जाती है, जिससे रोगी में खून बनना बंद हो जाता है। नतीजन लाल रक्त कोशिकाओं के न बनने के कारण अनीमिया, घटती श्वेत रक्त कोशिकाओं के कारण इंफेक्शन और घटते प्लेटलेट्स के कारण छोटी से छोटी चोट में भी खून का बहना न रुकना। डॉक्टर ऐसे में एजाथायोप्रीन देने से पहले रोगी के टीपीएमटी जीन की जांच करा सकते हैं कि मरीज में कहीं यह जीन अलग तो नहीं। अगर कोई बदलाव उन्हें मिलता है तो वे ऐसे मरीजों को एजाथायोप्रीन नहीं देते और रोगी इसके गंभीर साइड इफेक्ट से बच जाता है। ये दो उदाहरण उन दवाओं के थे, जिनसे लोगों को साइड इफेक्ट हुआ करते हैं। लेकिन इसके अलावा दवा से मिलने वाले लाभ भी हर व्यक्ति में अलग-अलग होने की वजह कोशिकाओं में जीनों के भिन्न-भिन्न प्रकारों की मौजूदगी है। इन्हें पहचान कर अलग-अलग रोगी को अलग-अलग दवा देने से उसे बेहतर फायदा हो सकता है। इस तरह से किया गया उपचार कस्टमाइज्ड या व्यक्तिगत उपचार है, जिसमें प्रमुख भूमिका उस व्यक्ति का जेनेटिक मेकअप निभाता है। सभी जीनों को सामूहिक रूप से हम जीनोम कहते हैं। दवाओं के अध्ययन को फार्माकोलॉजी नाम दिया गया है। ऐसे में जीनोम के अनुसार रोगी के लिए दवा के व्यक्तिगत चुनाव को फार्मैकोजीनोमिक्स नाम दिया गया है। यह एक ऐसी विधा है, जिसमें मरीज की जेनेटिक बनावट के अनुसार उसके लिए दवा का निर्माण और इस्तेमाल किया जाता है।